

आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 06.05.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :-

- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने पिटकूल को देहरादून में बिजली लाइनों की भूमिगत केबलिंग, सड़कों की खुदाई और ब्लैक टॉपिंग का कार्य जून माह तक पूरा करने के निर्देश दिए।
- जनगणना निदेशक इवा श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में मकानों की गणना कार्य की नियमित निगरानी के साथ ही उच्च स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जा रही है।
- वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के सीमावर्ती जादूंग गांव को फिर से आबाद करने के लिए होम स्टे बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
- दून अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एकीकृत निदान केंद्र शुरू। मरीजों को जांच से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सड़कों की खुदाई, भूमिगत केबलिंग और ब्लैक टॉपिंग का कार्य जून माह तक पूरा करने के पिटकूल को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने आज सचिवालय में देहरादून में बिजली लाइनों की भूमिगत केबलिंग को लेकर ऊर्जा विभाग और जिलाधिकारी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने पिटकूल को सभी स्थानों पर एक साथ काम शुरू करने के बजाय अपने सभी श्रमिकों को कुछ स्थानों पर केंद्रित करके कार्यों को निर्धारित समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे पूरे शहर की सड़कें खुदने के बजाय कुछ हिस्सों में अधिक श्रमिक लगाने से कार्य ज्यादा तेजी से होगा। इससे शहरवासियों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को भी भूमिगत केबलिंग की प्रगति की साप्ताहिक निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक जगह कार्य पूरा होने के बाद ही आगे के कार्य शुरू किए जाने की अनुमति देने के भी निर्देश दिए।

मकानों की गणना

प्रदेश में मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया के तहत प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। संबंधित प्रशासन की ओर से इसकी लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारु बनी रहे। जनगणना निदेशक इवा श्रीवास्तव के अनुसार इस कार्य की नियमित निगरानी की जा रही है और उच्च स्तर पर भी इसकी समीक्षा हो रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि प्रगणकों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का सटीक और सही जवाब दें और

किसी भी तरह की घबराहट न रखें। यह पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है और दी गई जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है।

मकान गणना/पौड़ी

उधर, पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में सभी तहसीलों और नगर निकायों में चल रही मकानों की गणना और मकान सूचीकरण कार्यों की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण 24 मई तक निर्धारित है, लेकिन जिले के सभी चार्ज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि फील्ड का सभी कार्य 20 मई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि समय से पहले लक्ष्य प्राप्ति से डेटा की जांच और तकनीकी त्रुटियों के सुधार के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपनी कार्ययोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से जनगणना कार्य को गंभीरता के साथ पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाए रखें, ताकि यह महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

कैबिनेट मंत्री

ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को मजबूती देकर उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। रुद्रप्रयाग में आयोजित एक बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, खादी ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए। पहाड़ी उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना जरूरी है। गांव आत्मनिर्भर होंगे, तो प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा। बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया।

होम स्टे

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के सीमावर्ती जादूंग गांव को फिर से आबाद करने के लिए होम स्टे बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वर्ष 2024 में पहले चरण में करीब तीन करोड़ 65 लाख रुपए की लगात से छह होमस्टे का निर्माण शुरू किया गया था।

पहाड़ी शैली में बनाए जा रहे इन होमस्टे के निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। वहीं, दूसरे चरण में आठ और होमस्टे के निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। इन होमस्टे की चिनाई में पुराने भवनों में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। कार्यदायी संस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम से मिली जानकारी के अनुसार यहां छह होमस्टे में से दो पर पटाल की छत डाल दी गई है। वहीं, अन्य होमस्टे में पटाल की छत डालने सहित अन्य काम होने शेष हैं। इसके बाद इन होमस्टे के अंदर फिनिशिंग का काम किया जाएगा। होमस्टे में एक कमरा भूतल पर और एक ऊपरी मंजिल पर रहेगा। भूतल में होमस्टे स्वामी और ऊपरी मंजिल पर पर्यटकों के ठहरने की उचित व्यवस्था रहेगी। जादूंग गांव में पहले चरण में निर्माणाधीन होमस्टे के लिए करीब 40 श्रमिक जुटे हुए हैं। वहीं, दूसरे चरण में शुरू किए गए आठ होमस्टे के निर्माण के लिए 20 श्रमिकों को लगाया गया है। होमस्टे निर्माण में लगे कुछ श्रमिकों के रहने के लिए जादूंग में ही टिनशेड बनाए गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में सीमावर्ती जादूंग गांव को खाली करवाया गया था। अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत गांव को दोबारा बसाने के उद्देश्य से गांव के मूल निवासियों के लिए होमस्टे बनावाये जा रहे हैं।

डायग्नोस्टिक सेंटर

दून अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल के तहत एकीकृत निदान केंद्र की शुरुआत की गई है। इसके शुरू होने से मरीजों को जांच से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं। दून अस्पताल के गेट नंबर- तीन पर संचालित इस केंद्र में मरीजों को अब एक ही काउंटर पर पर्ची बनाने से लेकर जांच रिपोर्ट प्राप्त करने तक की सुविधा मिल रही है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रविन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि न केवल मरीज, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति भी अपनी फिटनेस जांच के लिए इस केंद्र का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र में सभी जांचें सरकारी दरों पर उपलब्ध हैं, जिससे आम जनता को किफायती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।

हरिद्वार सीवर लाइन

हरिद्वार में गंगा नदी की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक सीवरेज परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड पेयजल निगम की ओर से संचालित इस परियोजना के तहत 206 किलोमीटर लंबी सीवर लाइनें बिछाई जा रही हैं। करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इस योजना के पूरा होने पर 15 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन जोड़े जाएंगे, जिससे लगभग चार लाख की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार इस योजना से न केवल गंगा में प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि भूजल संरक्षण और शहर की स्वच्छता व्यवस्था में भी सुधार होगा। यह परियोजना तीर्थनगरी में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए भी बेहतर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

चारधाम यात्रा

प्रदेश में चारधाम यात्रा आस्था और भक्ति के साथ सुगम व सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। अब तक सात लाख पचास हजार से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। सर्वाधिक तीन लाख 44 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं, जबकि लगभग दो लाख श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। वहीं, उत्तरकाशी जिले स्थित यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में दो लाख बारह हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की है। इस बीच, यात्रियों के आवागमन का क्रम लगातार जारी है।